

आज शुरू होगा 'स्टार्टअप इंडिया', कारोबारी चाहते हैं समान मौके

■ पीएम करेंगे अभियान की शुरुआत, सिलिकॉन वैली के 40 सीईओ-निवेशक भाग लेंगे
भास्कर न्यूज़/नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। युवा कंपनियों को संकेत देने के लिए वह मंच पर अपने मंत्रियों के साथ नहीं, बल्कि इन कंपनियों के प्रमुखों के साथ खड़े दिखेंगे। प्रयास यह भी किया जा रहा है कि मंच से ही स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की जाए। स्टार्टअप इन प्रयासों को बेहतर मान रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि सरकार उन्हें नियमित और बड़ी कंपनियों की तरह समान अवसर दे। साथ ही ऐसा तंत्र विकसित हो जिससे उन्हें सरकार की

सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।

निवेशकों के एक संगठन 'ट्राई सिलिकॉन वैली' के प्रेसिडेंट वेंकटेश शुक्ला ने कहा, 'स्टार्टअप के लिए ऐसे जुटाने के नियम सरल होने चाहिए। बहुत से स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। उनके लिए कंपनी बंद करने का नियम भी आसान होना चाहिए।'

इन्वेंटस कैपिटल के एमडी कंवल रेखी ने कर कानूनों में भेदभाव का जिक्र किया। बोले, 'पूंजी बाजार में पैसा लगाने पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन स्टार्टअप में निवेश पर टैक्स लगता है। इसी तरह मॉरीशस से निवेश टैक्स-फ्री है, जबकि अमेरिका से होने वाला निवेश टैक्स के दायरे में आता है। हम प्रोक्ष तरीके से निवेश नहीं करना चाहते हैं। हम सीधे सिलिकॉन वैली से भारत में निवेश करना चाहते हैं।'

गूगल ने पांच सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप का चयन किया है। ये सब 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इनमें से तीन स्टार्टअप के साथ भास्कर ने सीधी बात की। जानने की कोशिश की सरकार से वे क्या चाहते हैं-

प्रमुख मांगें



- स्टार्टअप के लिए ऐसे जुटाने के नियम सरल होने चाहिए।
- कंपनी खोलने और बंद करने के नियम आसान होने चाहिए।
- मॉरीशस की तरह अमेरिका से निवेश पर भी टैक्स न लगे।
- सस्ता कर्ज, 3 साल तक टैक्स से छूट, सरकारी परियोजनाओं में शामिल किया जाए।

गुरुजी लर्निंग लैब्स

शिवानंद सलगामे
सह-संस्थापक

हम समान अवसर चाहते हैं। सरकार अपने टेंडर में कहती है कि कंपनी इतने साल पुरानी हो। उसका इतना टर्नओवर हो। जैसे स्कूलों में आईसीटी योजना है। उसमें पुरानी कंपनियां हैं। उनका तरीका पुराना है। हम चाहते हैं कि नए लोगों को नए तरीके से काम करने का मौका मिले। आईसीटी योजना बेमानी है। सरकार को टर्नओवर-कंपनी के पुराने होने जैसे नियम खत्म करने चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी स्टार्टअप को मिले, इसके लिए बेहतर सूचना तंत्र स्थापित हो।

स्लेमडंग

मधुवंती, संस्थापक
सखी, सह-संस्थापक

हमारी कंपनी खेल से जुड़ी क्षमता के आकलन के लिए स्मार्ट घड़ी और अन्य गैजेट बनाती है। हम चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं की सूचना का एक मंच हो। सभी स्टार्टअप को यहीं से हर तरह की जानकारी मिल जाए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि फंड आदि कहां से मिल सकता है। ऐसा होने पर ही नए लोगों को मौका मिलेगा। अमेरिका में 70% नौकरियां छोटी कंपनियां पैदा करती हैं। यह मॉडल भारत में भी अपनाया जा सकता है।

कार्डिक डिजाइन लैब्स

आनंद मदनगोपाल
संस्थापक एवं सीईओ

अभी दिल से संबंधित परीक्षण की मशीन केवल बड़े शहरों और अस्पतालों में है। हमारी मशीन 30-40 हजार रुपये की है। हम प्रति यूजर के हिसाब से चार्ज करते हैं। न्यूनतम चेकअप 50 रुपये में संभव है। लेकिन हमारे पास फंड की कमी है। हम चाहते हैं कि सरकार उन स्टार्टअप को फंड मुहैया कराए जो चल सकते हैं। सरकार ने 10 हजार करोड़ रु. के वेंचर फंड की बात की थी। उसका उपयोग इसके लिए होना चाहिए। इससे लोगों को नई तकनीक से तेजी से समस्याओं का सस्ता निवारण हासिल हो पाएगा।